सान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02 | अंक - 289 | जौनपुर, मंगलवार, 16 जुलाई 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

शिक्षक अड़े, मांगे नहीं माने जाने तक हाजिरी नहीं

लखनऊ, संवाददाता। डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में आंदोलनरत बेसिक के शिक्षकों ने सोमवार को एकजुटता दिखाई। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले स्कूल समय के बाद प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षक जुलूस की शक्त में जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि उनकी ईएल, सीएल, हाफडे, मेडिकल जैसी मांगे मानी जाने तक वह डिजिटल अटेंडेंस का बहिष्कार जारी रखेंगे। वहीं विभागीय असहयोग के तहत हजारों शिक्षकों ने अलग–अलग जिलों में शिक्षक संकुल के पद से सामूहिक इस्तीफा दिया। शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जौनपुर, बरेली, औरैया, झांसी, फिरोजाबाद, गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी, रामपुर, कन्नौज, चित्रकूट, कुशीनगर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, ललितपुर, हाथरस, प्रतापगढ़ आदि जिलों में काफी संख्या में शिक्षकों ने पैदल मार्च निकालकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। इनका नेतृत्व प्राथमिक शिक्षक संघ, यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा), जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ, अटेवा, शिक्षामित्र संघ व विशिष्ट बीटीसी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने किया। संयुक्त मोर्चा के संयोजक व यूटा के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह राठौर ने बताया कि आंदोलन की अगली कड़ी में अगले तीन दिन जिला स्तर पर शिक्षक जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देंगे।

निर्विरोध चुने गए नगर निगम कार्यकारिणी के सदस्य

लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी के खाली छह पदों पर भाजपा के पांच और सपा के एक प्रत्याशी को निर्विरोध चुन लिया गया। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। चुनाव को लेकर भाजपा ने पांच और सपा ने एक प्रत्याशी का नाम तय किया था। नगर निगम की 12 सदस्यीय कार्यकारिणी के छह सदस्य 14 जून को लाटरी डालकर रिटायर किए गए थे। उन्हीं रिक्त पदों पर चुनाव हुआ। जो छह सदस्य रिटायर हुए थे, उनमें भाजपा के पांच और सपा का एक सदस्य शामिल था। उसी हिसाब से दोनों दलों ने प्रत्याशी तय किए हैं, ताकि क्रॉस वोटिंग और चुनाव की नौबत न आए।

भाजपा के चुने गए सदस्यों में बाबू जगजीवन राम वार्ड के पार्षद भृगुनाथ शुक्ला, कुंवर ज्योति प्रसाद वार्ड की गौरी सांवरिया, मोती लाल नेहरू चंद्रभानु गुप्त वार्ड की चरनजीत गांधी, बाजार कालीजी चौक के अनुराग मिश्रा अन्नू और खरिका प्रथम वार्ड के कृष्ण कुमार का नाम शामिल हैं।

वहीं, सपा की अंबरगंज वार्ड की पार्षद सबा अहसन को चुना गया है। कांग्रेस के सदन में महज तीन पार्षद हैं। ऐसे में वह चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थी।

मीटर जांच या बकाया की वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं

लखनऊ, संवाददाता। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीते सात वर्षों में प्रदेश में सबको बिजली–निर्बाध बिजली का संकल्प पूरा हो रहा है। हर गांव–हर मजरे तक बिजली उपलब्ध पहुंचाई गई है। यह सुखद है कि आज बिना किसी भेदभाव अथवा वीआईपी कल्चर के आपूर्ति की जा रही है। इस बार भीषण गर्मी के बीच आमजन की सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हुए 15 मार्च से 30 जून तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की गई। विभिन्न हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट के अतिरिक्त आज प्रदेश में अनपरा, हरदुआगंज, ओबरा, पारीछा और जवाहरपुर में 22 थर्मल परियोजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। घाटमपुर, पनकी, ओबरा–सी और जवाहरपुर में निर्माणाधीन इकाइयों का कार्य तेजी के साथ पूरा करा लिया जाए। एनटीपीसी के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित हो रही ओबरा डी, अनपरा ई और मेजा तापीय परियोजना–द्वितीय चरण के अलावा, टीएचडीसी के साथ निर्माणाधीन खुर्जा तापीय परियोजना का कार्य तेज किये जाने की अपेक्षा है। इन प्रयासों से प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। रिहंद बांध, ओबरा जलाशय तथा इसके आस पास के क्षेत्र में पम्प स्टोरेज प्लांट स्थापित किये जाने की संभावना का अध्ययन कराया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2018–19 में एक दिन में सर्वाधिक 20062 मेगावॉट की मांग रही, जो इस सत्र में 13 जून को 30618 मेगावॉट तक पहुंच

गई थी। आमजनता की आवश्यकता के दृष्टिगत इस वर्ष गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति की गई। मांग के सापेक्ष पर्याप्त बिजली आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित कराएं। हर घर बिजली–निर्बाध बिजली के संकल्प की पूर्ति में विद्युत पारेषण तंत्र को और बेहतर किया जाना आवश्यक है। नए सब स्टेशन स्थापित करने से पूर्व वहां की आवश्यकता का अध्ययन जरूर किया जाए। अगले पांच वर्ष की आवश्यकता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करते हुए नए सब स्टेशनों की स्थापना कराई जाए।

बिना विलंब सुधारे जाएं ट्रांसफार्मर

मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि गांव हो या नगरीय क्षेत्र ट्रांसफार्मर खराब हो तो बिना विलंब तत्काल सुधार होना चाहिए। आवश्यकतानुसार नया ट्रांसफार्मर भेजा जाए। तय समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने वाली एजेंसियों के कार्यों का भी अवलोकन किया जाना चाहिए। टॉल फ्री नंबर/हेल्पलाइन पर आने वाली हर कॉल अटेंड करें। हर उपभोक्ता की समस्या का यथोचित समाधान किया जाना चाहिए। बिजली कनेक्शन चार्ज तय करने को लेकर प्रायः लोगों में असंतुष्टि देखी गई है। यह आवश्यक है कि इसमें एकरूपता हो। इसके लिए नियमों में सुधार करें। अनावश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को कम किया जाए। आम जन की सुविधा और सहूलियत को प्राथमिकता दें।

पॉवर कॉर्पोरेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सही बिल और समय पर बिल उपलब्ध कराना तथा सभी उपभोक्ताओं से बिल की राशि का संग्रह करना। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी उपभोक्ता को गलत बिजली बिल न मिले और सभी को समय से बिल मिल जाए। ओवरबिलिंग अथवा विलंब से बिल दिया जाना उपभोक्ता को परेशान तो करती ही है, व्यवस्था के प्रति निराश भी करती है और वह बिल जमा करने के प्रति उत्साहित नहीं होता।

मैं पहले बीजेपी नेता बाद में डिप्टी सीएम

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य पर सभी की नजर है। उनके हर कदम को लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद वह काफी खामोश नजर आ रहे हैं। उपमुख्यमंत्री होने के बाद भी सरकार के कामों में उनकी दिलचस्पी नहीं दिख रही। यहीं कारण हैं कि उनको लेकर संगठन में वापसी की चर्चा जोरो पर है। वहीं, मौर्य ने भी अपने एक बयान में सरकार से ज्यादा पार्टी संगठन की प्रधानता पर जोर दिया है। भाजपा की एक दिवसीय राज्य कार्यसमिति की बैठक के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी की संरचना और उसका कैडर हमेशा सरकार से अधिक महत्व रखेगा। मौर्य ने कहा कि सभी मंत्रियों, विधायकों और जन प्रतिनिधियों को पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी गरिमा बरकरार रहे। अपने भाषण में, मौर्य ने हालिया लोकसभा चुनाव परिणामों पर विचार

किया और स्वीकार किया कि वे पार्टी की उम्मीदों से कमतर रहे। उन्होंने इन चुनावी असफलताओं के लिए विपक्ष द्वारा प्रचारित झूठ और धोखे को जिम्मेदार ठहराया। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाजपा ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन के संबंध में लखनऊ में गहन विश्लेषण किया और परिणाम से संबंधित हर प्रमुख बिंदु की पहचान करने का प्रयास किया। सभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुर्खियां बन गया है। बैठक में मौर्य ने कहा कि वह खुद को पहले भाजपा कार्यकर्ता मानते हैं फिर उप मुख्यमंत्री। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संगठन सदैव सर्वोच्च था, है और रहेगा। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि जो भी होता है घटनाक्रम,रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही, कल पुरस्कार बन जाता हैं निश्चित होगा प्रबल समर्थन,अपने सत्य विचार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता,कभी जीत और हार का कार्यकर्ता ही मेरा गौरव व मेरा अभिमान है। उन्होंने कहा कि झूठ की मशीन बन चुके विपक्ष को जवाब देने का समय आ गया है। 2027 में अगर सपा, बसपा और कांग्रेस एक भी हो जाएं तो भी हमें अपनी ताकत के दम पर 300 (403 सीटों में से) का लक्ष्य पार करना होगा. 2024 में जो भी कमी रह जाएगी

अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे केजरीवाल, ईडी की याचिका पर 7 अगस्त तक टली सुनवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका सोमवार को 7 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दी। उच्च न्यायालय ने पहले निचली अदालत के 20 जून के आदेश पर रोक लगा दी थी जिसके द्वारा केजरीवाल को मामले में जमानत दी गई थी। जो याचिका पर सुनवाई करने वाली थीं, को केजरीवाल के वकील ने सूचित किया कि ईडी ने उन्हें रविवार देर रात ही अपने प्रत्युत्तर की एक प्रति दी थी और उन्हें इसका जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है और वे आदेश की प्रति रिकॉर्ड में रखेंगे। वकील ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 7 अगस्त को सूचीबद्ध किया है। 20 जून को केजरीवाल को यहां एक ट्रायल कोर्ट ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। ट्रायल कोर्ट का आदेश विकृत, एकतरफा और गलत–पक्षीय था और निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे। ईडी की याचिका का विरोध करते हुए, केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है कि वह जांच एजेंसी द्वारा विच–हंट का शिकार थे और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उनकी जमानत रद्द करना न्याय की गंभीर हत्या के समान होगा। जमानत के विवेकाधीन आदेशों को केवल अभियोजन पक्ष की धारणाओं और काल्पनिक कल्पना के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

बाढ़ को लेकर एक्शन मोड में अमित शाह

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात कर तीनों राज्यों में बाढ़ और भारी बारिश के कारण उपजी स्थिति का जायजा लिया

तथा उन्हें केंद्र से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत में शाह ने राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। शर्मा ने शाह को मौजूदा स्थिति और अब तक उठाए गए कदमों से अवगत कराया।

हरसंभव मदद मुहैया कराने का दिया आश्वासन

सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर हुई बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री ने दोनों राज्यों में भारी बारिश के बाद नदियों में बढ़ते जलस्तर के कारण उपजी स्थिति का जायजा लिया। सूत्रों के अनुसार, शाह ने तीनों मुख्यमंत्रियों को स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया।

असम में अबतक 109 लोगों की मौत

असम में बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 109 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य के कछार, चिरांग, दरांग, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़, गोलपाड़ा, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, करीमगंज, माजुली, मोरीगांव, नागांव, नलबाड़ी और शिवसागर जिलों में 5,97,600 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में लगभग 1,500 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और बारिश से संबंधित घटनाओं में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

पीएम मोदी से मिले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन

नई दिल्ली, एजेंसी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पांच महीने जेल में बिताने और जेल से रिहा होने तथा फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली मुलाकात थी। आपको बता दें कि झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इस चुनावी मौसम के बीच, झारखंड के मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा और पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात ने कई चर्चाओं को जन्म दिया है। इससे पहले 13 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह ने झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की थी। सोरेन ने राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। कांग्रेस और झामुमो इंडिया

गुट में सहयोगी हैं और लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े थे। 8 जुलाई को, तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ दिनों बाद, सोरेन ने राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान फ्लोर टेस्ट जीता। हेमंत सोरेन ने अपने पक्ष में 45 विधायकों के वोट के साथ विश्वास मत जीत लिया। अपनी गिरफ्तारी को लेकर हेमंत सोरेन लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावा रहे है। वह भाजपा पर आदिवासियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि झारखंड से भाजपा का सफाया हो जाएगा। हालांकि इन सब के बीच उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है।

मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के साथ शिष्टाचार मुलाकात थी। कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तारी से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लगभग पांच महीने जेल में बिताने के बाद, उन्हें जमानत मिल गई और 4 जुलाई को फिर से मुख्यमंत्री बन गए। झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया वह अपराध के लिए दोषी नहीं हैं और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि जमानत पर रहते हुए वह कोई अपराध करेंगे।

अपनी सरकार बचाने के लिए गहलोत ने अवैध फोन टैपिंग करवाई – शेखावत

राजस्थान, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके तत्कालीन विशेषाधिकारी के बीच कथित बातचीत का ऑडियो क्लिप ऑनलाइन सामने आने के बाद रविवार को उन पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत पर अपनी सरकार बचाने के लिए अवैध 'फोन टैपिंग' का सहारा लेने का आरोप लगाया। गहलोत के तत्कालीन विशेषाधिकारी (ओएसडी) लोकेश शर्मा ने अप्रैल में एक संवाददाता सम्मेलन में उनके और गहलोत के बीच बातचीत की कथित कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी। उन्होंने दावा किया था कि 2020 में शेखावत और कुछ कांग्रेस नेताओं के बीच राज्य की कांग्रेस सरकार को 'गिराने' के लिए टेलीफोन पर हुई कथित बातचीत की क्लिप तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें एक पेन ड्राइव में दी थी।

शर्मा, शेखावत द्वारा दिल्ली में दर्ज अवैध तरीके से फोन टैपिंग से संबंधित मामले में आरोपी हैं। गहलोत और शर्मा के बीच कथित बातचीत की एक कॉल रिकॉर्डिंग हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शेखावत ने रविवार को कहा, ''पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार बचाने के लिए फोन टैपिंग का सहारा लिया था। उन्होंने फोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया और इसे सार्वजनिक करने के लिए इसे पेन ड्राइव में 'सेव' कर लिया।

प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य सेवा जैसी चुनौतियों से मिलकर निपटना होगा - एस जयशंकर

नई दिल्ली, एजेंसी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने जलवायु परिवर्तन को एक बड़ी चुनौती माना है। इसके साथ ही इससे मिलकर लड़ने की अपील दुनिया से की है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य सेवा बड़ी चुनौतियां हैं, जिनका हमें मिलकर समाधान करना होगा। उन्होंने मार्शल द्वीप समूह के साथ हुए समझौते पर एक बयान जारी किया। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। कहा, "मार्शल द्वीप समूह गणराज्य के साथ चार सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए वार्षिक अनुदान सहायता संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर यह संदेश देना मेरे लिए खुशी की बात है। भारत के लोगों की ओर से मैं पिछले महीने मार्शल द्वीप में संपन्न हुए 10वें माइक्रोनेशन गेम्स के सफल आयोजन

के लिए बधाई देना चाहता हूं।" विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि पिछले महीने जून में 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मैं माजुरो में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करने के लिए मार्शल द्वीप की राष्ट्रपति डॉ. हिल्डा हैन को धन्यवाद देता हूं। भारत और मार्शल द्वीप गणराज्य के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पिछले कुछ वर्षों में भारत–प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के सहयोग से और भी मजबूत हुआ है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे एफआई पीईसी शिखर सम्मेलन में क्या कहा था। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप छोटे द्वीप नहीं हैं, बल्कि ये बड़े महासागरीय देश हैं। हम सतत विकास की खोज में प्रशांत महासागर के द्वीपों का समर्थन करने को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य सेवा बड़ी चुनौतियां हैं, जिनका हमें मिलकर समाधान करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशांत द्वीप समूह के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की। उन्हें हासिल करने में हुई प्रगति को देखकर मुझे खुशी हो रही है।

असम में सीएए के तहत केवल आठ लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया – सीएम हिमंत

असम, एजेंसी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बताया कि राज्य से अब तक केवल आठ लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुएबताया कि इन आवेदकों में से केवल दो ही व्यक्तियों ने संबंधित अधिकारियों को साक्षात्कार दिया है। राज्य की बराक घाटी में इस संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई हिंदू बंगाली परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया।

संपादकीय

यूरोप का इकारस

यूरोप के लिए यह एक अच्छा सप्ताह था। यूरोप के लिए यह एक बुरा सप्ताह था। अच्छा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में अब एक मजबूत, स्थिर, मध्यमार्गी सरकार है जो यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए उत्सुक है और फ्रांस में मतदाताओं ने कट्टर–दक्षिणपंथी राष्ट्रीय रैली को सत्ता से बाहर रखने के लिए रैली की। बुरा इसलिए क्योंकि फ्रांस में एक कमजोर, अस्थिर, विभाजित सरकार का दौर शुरू होने वाला है, जो पूरे यूरोपीय संघ को बाधित करेगा। यह हमारे महाद्वीप के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन अभी भी यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रम्प के फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की संभावना है जब तक कि जो बिडेन अपने पद से हट नहीं जाते। फिर से उदास होने से पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। ब्रिटेन में अब केंद्र–वाम की एक जिम्मेदार, व्यावहारिक सरकार है जिसे पाँच साल तक के लिए चुना गया है। इसका नेतृत्व एक मानवाधिकार वकील कर रहा है जो घर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून के शासन की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैय बाजार अर्थव्यवस्था, राज्य के हस्तक्षेप और सामाजिक न्याय के विवेकपूर्ण मिश्रण को अपनाता हैय यूक्रेन का दृढ़ता से समर्थन करता है और अन्य यूरोपीय देशों के साथ अच्छे संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वास्तव में, यह यूरोपीय संघ की संधि के अनुच्छेद 2 में घोषित मूल्यों से यूरोपीय संघ के सदस्य देश हंगरी की सरकार की तुलना में कहीं बेहतर मेल खाता है, जिसके उदारवाद विरोधी राष्ट्रवादी नेता विक्टर ओर्बन हाल ही में मास्को में पुतिन के साथ बैठकर यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वे यूक्रेन को 'शांति' के नाम पर कैसे मजबूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पेच यह हैरू ब्रिटेन (यदि आपने ध्यान नहीं दिया है) अब यूरोप के मुख्य राजनीतिक और आर्थिक समुदाय का सदस्य नहीं है। जैसे कि पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर की दौड़ के लिए प्रशिक्षण ले रहे हों, ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड लैमी ने अपने कार्यकाल के पहले तीन दिनों में ही जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन में अपने समकक्षों से मुलाकात की। इस बीच, नए रक्षा मंत्री जॉन हीली अपने यूक्रेनी समकक्ष से बातचीत के लिए ओडेसा पहुँच गए। लैमी ने यूरोपीय संघ और अलग–अलग यूरोपीय देशों के साथ "रीसेट", "नई शुरुआत" और "घनिष्ठ साझेदारी" का जोरदार और वाक्पटु आह्वान किया है। ब्रिटेन ने एक नए यूके–ईयू सुरक्षा समझौते का प्रस्ताव रखा है और कई क्षेत्रों में निकट सहयोग की उम्मीद करता है। बर्लिन, पेरिस, वारसॉ और अन्य यूरोपीय राजधानियों में बहुत सद्भावना व्यक्त की गई है। लेकिन तथ्य यह है कि यूनाइटेड किंगडम संस्थागत रूप से यूरोपीय संघ के लिए सिर्फ एक और श्तीसरा देशश है, इसका मतलब है कि इस नए, करीबी रिश्ते पर बातचीत करने की प्रक्रिया जटिल होगी, जिसमें यूरोपीय संघ के अंदर कई राष्ट्रीय, पार्टी–राजनीतिक और नौकरशाही खिलाड़ियों के लिए कई अवरोध या वीटो की संभावनाएं होंगी। इसके अलावा, ब्रेक्सिट समर्थक मतदाताओं को लेबर में वापस लाने के लिए कीर स्टारमर ने जो लाल रेखाएँ घोषित कीं – यूरोपीय संघ के सीमा शुल्क संघ, एकल बाजार या आंदोलन की स्वतंत्रता में कोई वापसी नहीं – आर्थिक मोर्चे पर जो कुछ भी किया जा सकता है उसे गंभीर रूप से सीमित करती हैं। और ब्रिटिश राजनीति महाद्वीपीय यूरोप की राजनीति से उतनी अलग नहीं है जितनी पहली नजर में लगती है। लेबर की जीत के पैमाने का एक मुख्य कारण यह था कि दक्षिणपंथी वोट कंजरवेटिव और निगेल फरेज के रिफॉर्म यूके के बीच विभाजित हो गया था, जो ब्रिटिश – या अधिक सटीक रूप से, अंग्रेजी – मरीन ले पेन की नेशनल रैली, जर्मनी के एएफडी या इटली के फ्रेटेली डीश्इटालिया के समकक्ष है, जो व्यापक लोकप्रिय आर्थिक और सांस्कृतिक चिंताओं को आव्रजन के बलि का बकरा बनाने में लगा रहा है। फरेज के फ्रेटेली डी इंग्लैंडेरा – या, यदि आप चाहें तो, अल्टरनेटिव फर इंग्लैंड – को 14: लोकप्रिय वोट मिले, जबकि टोरीज को 24: मिले। चौनल के दोनों ओर राष्ट्रवादी लोकलुभावन भावनाएँ यूके–ईयू रीसेट को बाध्ित और जटिल करेंगी, जबकि दोनों तरफ कट्टर–दक्षिणपंथी मजबूत हो रहे हैं। फिर भी, लंदन से आई खबर पेरिस से मिली खबर से अधिक उत्साहजनक है। हां, हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहे एक अंतरिक्ष यात्री ने रविवार शाम को फ्रांसीसी समयानुसार रात 8 बजे पूरे यूरोपीय महाद्वीप से राहत की एक बड़ी सांस सुनी होगी, क्योंकि हमें पता चला कि नेशनल रैली ने इस संसदीय चुनाव के पहले दौर में अपनी शानदार सफलता को दोहराया नहीं है और यह फ्रांसीसी संसद के निचले सदन, नेशनल असेंबली में केवल तीसरा सबसे बड़ा समूह होगा। लेकिन यहीं पर अच्छी खबर खत्म हो जाती है। यदि, ब्रिटेन में, लोकप्रिय वोट सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से कंजर्वेटिवों को बाहर निकालने के लिए था, तो फ्रांस में यह नेशनल रैली को बाहर रखने के लिए था, किसी विशेष व्यक्ति को अंदर नहीं लाने के लिए। परिणामस्वरूप संसद तीन मुख्य समूहों में विभाजित हो गईरू जल्दबाजी में बनाया गया न्यू पॉपुलर फ्रंट, चार बहुत अलग–अलग पार्टियों का एक ढीला वामपंथी गठबंध्ान, जिसमें यूरोसेप्टिक, लोकलुभावन फ्रांस अनबोड शामिल हैय इमैनुएल मैक्रोन का मध्यमार्गी एनसेंबल, जो वास्तव में एक पार्टी नहीं है, बस एक समूह हैय और नेशनल रैली, जो एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है। किसी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है।

आम आदमी के लिए नए आपराधिक संहिता कानूनों का महत्व

आदित्य

अंग्रेजी दार्शनिक जेरेमी बेंथम द्वारा स्थापित नैतिक व्यवस्था को सबसे लंबे समय तक 'सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा लाभ' के उनके सिद्धांत में समाहित किया गया है। वास्तव में, यह सरकारों के लिए एक लक्ष्य है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनकी नीतियों का मूल्यांकन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा, और अधिक सटीक रूप से, चाहे वे बहुमत को लाभ पहुँचाएँ या नहीं। बेंथम के इस 'उपयोगितावाद' के विचार को जॉन स्टुअर्ट मिल ने 'सबसे बड़ी खुशी के सिद्धांत' के रूप में आगे बढ़ाया, जिसका दर्शन 'सबसे बड़ी संख्या में लोगों के लिए सबसे बड़ा लाभ' की रक्षा करना है। भारत में 'भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)' के रूप में जाने जाने वाले 'नए आपराधिक संहिता कानूनों' की शुरूआत के साथ 'भारतीय कानूनी परिदृश्य' में हाल ही में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन के संदर्भ में, बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल और भी अधिक प्रासंगिक हैं। 12 दिसंबर, 2023 को, बीएनएस विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। 20 दिसंबर, 2023 को इसे लोकसभा में पारित किया गया और अगले दिन इसे राज्यसभा में पारित किया गया। यह 1 जुलाई, 2024 को देश की 'नई दंड संहिता' के रूप में लागू हुआ, जो ब्रिटिश भारत के समय की 'भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)' की जगह लेगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें पुराने शब्द हैं और यह आधुनिक जरूरतों को पूरा नहीं करता। बीएनएस की मुख्य विशेषताएं मूल रूप से विशिष्ट भारतीय शैली की 'संस्कृत शब्दावली और परिभाषाएं' हैं जैसे राष्ट्रद्रोह, असमायिक सभा, हत्या, चोरी, धार्मिक भावना भंगन, बलात्कार, साइबर अपराध, अपमान आदि। यह आपराध्िक कानूनों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को अद्यतन और आध्ुनिक बनाता है। यह साइबर अपराध्ा, संगठित अपराध और वित्तीय ध्ाोखाधड़ी जैसे समकालीन अपराधों के लिए प्रावधान पेश करता है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध्ाों के लिए 'बढ़ी हुई और सख्त सजा' का भी प्रावधान है, जिसमें बलात्कार और यौन उत्पीड़न के लिए कठोर सजा शामिल है। कुल मिलाकर इन बदलावों का 'विपक्षी नेताओं और कुछ 'कानूनी पेशेवरों' ने कड़ा विरोध किया है। फिर भी, सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि इन नए नामकरण कानूनों का उद्देश्य "कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना, न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाना और समकालीन मुद्दों को संबोधित करना" है, जो पहले के कानूनों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी हैं। जैसा कि केंद्र सरकार ने बार–बार स्पष्ट किया है और इस बात पर जोर दिया है कि नए कानून 'प्रक्रियात्मक देरी' को कम करते हैं और 'न्यायिक प्रक्रिया' को सरल बनाते हैं। इसमें अदालती रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना, ई–फाइलिंग को बढ़ावा देना और वर्चुअल सुनवाई को सक्षम बनाना शामिल है। इन पहलों से मामलों के समाधान में तेजी आने और लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने की उम्मीद है। सरकार को यह भी विश्वास है कि पीड़ितों के अधिकारों और आपराधिक न्याय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, जिसमें पीड़ितों के मुआवजे, गवाहों की सुरक्षा कार्यक्रम, समय पर चिकित्सा जांच सुनिश्चित करना और यौन उत्पीड़न जैसे अपराध्ाों के पीड़ितों के लिए सहायता के प्रावधान शामिल किए जाएंगे। यह स्पष्ट किया गया है कि पुराने कानूनों में पीड़ितों को सीमित सहायता और सुरक्षा प्रदान की गई थी, जिससे अक्सर द्वितीयक उत्पीड़न होता था। सरकार के अनुसार, नए कानूनों का उद्देश्य जघन्य अपराधों के लिए कठोर दंड, बलात्कार, एसिड अटैक और मानव तस्करी के लिए कठोर सजाएँ पेश करना है, जो इन अपराधों के प्रति शून्य–सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पुराने कानून कुछ जघन्य अपराधों के लिए कम कठोर दंड तक सीमित हैं, जिससे जनता में आक्रोश और असंतोष पैदा होता है, ऐसा कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना घ्हहै। न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करने के लिए, नए कानूनों में, छोटे अपराधों को गैर–अपराधी या नागरिक उल्लंघन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे गंभीर अपराधों पर आवश्यक ध्यान और संसाधन उपलब्ध हो सके। इसके अलावा, यह कहा जाता है कि नए कानूनों का उद्देश्य अपराधियों के पुनर्वास और समाज में उनके पुनः एकीकरण को बढ़ावा देना है, जैसे कि छोटे अपराधों के लिए कारावास के विकल्प के रूप में सामुदायिक सेवा, परिवीक्षा और परामर्श। इस प्रकार, यह न्याय के सुधारात्मक पहलू को रेखांकित करता है। इन कानूनों पर थोड़ा और गहराई से विचार करने पर, और थोड़ा विश्लेषणात्मक रूप से, सरकार द्वारा सभी

सकारात्मक दावों के बावजूद, इनमें 'पक्ष और विपक्ष' या 'लाभ और हानि' हैं, जिन पर सरकार को ध्यानपूर्वक और निष्पक्ष रूप से विचार करने और संबोधित करने की आवश्यकता है, ताकि बेहतर और अधिक समझदार निर्णय लिया जा सके, जिसमें आवश्यकता–आधारित परिवर्तन शामिल हों। नए कानूनों की 'आवश्यकताएं, निहितार्थ और कार्यान्वयन' रणनीति, कानूनी दिग्गजों और मुखर विरोध की 'स्वीकार्यता और पहुंच' को सूचीबद्ध करने और सुनिश्चित करने के लिए, आम आदमी की बात तो दूर, एक परम आवश्यकता है। इस तरह से बेंथम की थीम 'सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा लाभ' और जॉन स्टुअर्ट मिल की 'सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा लाभ' की दर्शन को व्यावहारिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। नए कानून स्पष्ट रूप से अपराध से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हैं, उदाहरण के लिए निगरानी, घ्फ्कोरेंसिक विज्ञान और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग में, जो जांच क्षमताओं को बढ़ाने और अधिक सटीक और समय पर न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए शायद बहुत आवश्यक हैं। इस विचार के समर्थन में सरकार ने पुराने कानूनों को अप्रचलित, बोझिल और दुर्गम बताया।

बेहतर और कल्याणकारी नीतियां बन सकें

विनोद

हम वर्ष 2024 का आधा पड़ावघ्पार कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में वापसी कर चुकी है। लेकिन हर दस वर्ष में होने वाली जनगणना को लेकर अब तक कोई बात नहीं की जा रही। अंतिम बार जनगणना 2011 में हुई थी। भारत ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भी जनगणना करवाई थी, लेकिन 1981 से हर दस वर्ष में शुरू हुए जनगणना के क्रम को वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा। लेकिन, आश्चर्य की बात यह है कि चार साल बीत जाने के बावजूद हमारे पास अब भी जनगणना कराने के लिए समय नहीं है। बांग्लादेश और ब्राजील ने अपनी अंतिम जनगणना 2022 में संपन्न कराई थी। अमेरिका और चीन, तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी जनगणना 2020 में ही करवा चुके हैं।घ्जनगणना के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक देश के लोगों की संख्या और जनसांख्यिकीय व सामाजिक–आर्थिक विशेषताओं की जानकारियां बड़े स्तर पर जुटाई जाती हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन ऐंड डेवलपमेंट, केरल से संबंधित दो प्रतिष्ठित जनसांख्यिकीविद एस. इरुदया राजन और यूएस मिश्रा ने हाल ही में टिप्पणी की, कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में जनसंख्या की गणना वास्तविक नहीं है। दरअसल, भारत की जनसंख्या के ज्यादातर अनुमान दशकों पुराने आंकड़ों पर आधारित हैं। भारत जब तक अपनी समुचित जनगणना नहीं करा लेता, तब तक हमारे पास सिर्फ अनुमान ही होंगे। जनगणना में देरी के पीछे जो भी कारण हों, लेकिन जनगणना के आंकड़ों की कमी एक गंभीर मसला है। यह न केवल शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए नुकसानदेह है, बल्कि जनगणना के आंकड़ों में देरी की वजह से कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी प्रभावित होता है। जैसा राजन और मिश्रा भी इंगित करते हैं कि 'सटीक जनसंख्या और जनसांख्यिकीय संरचना को जानना महत्वपूर्ण है, ताकि हम बेहतर नीतियों का मसौदा तैयार कर सकें।' राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के अंतर्गतघ्देश के करीब 81.35 करोड़ लोगों को 31 दिसंबर, 2028 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। यह राशन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार दिया जा रहा है। सरकारघ्केघ्2019 के बयान के आधार पर देश की 67 फीसदी आबादी यानी 80 करोड़घ्लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के हकदार हैं। स्वतंत्र शोधकर्ताओं का अनुमान है कि मौजूदा समय में करीब 92 करोड़ लोग इस दायरे में आने चाहिए। अद्यतन जनसांख्यिकी आंकड़े मिलने पर एनएफएसए को लाभ मिलेगा। यह बात उन अज्ञात लाभार्थियों पर भी लागू होती है, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वृद्धावस्था पेंशन के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता से वंचित हैं। जनगणना के नवीनतम आंकड़े नहीं होने की कई चुनौतियां हैं। एक शोधकर्ता का कहना है कि यदि हमें बच्चों का टीकाकरण करना है, आंगनवाड़ी कहां खोलनी है या पीडीएस में कितने परिवारों को शामिल करना है, तो इसके लिए जनगणना की जरूरत है। यही जनसंख्या के आंकड़ों का एकमात्र स्वतंत्र स्रोत है, जिससे प्रशासन और गांव स्तर तक आबादी की विशेषताओं, जैसे–आयु, लिंग, परिवार का आकार आदि की जानकारी मिलती है। कई शोधकर्ताओं ने इस ओर ध्यान दिया है कि प्रशासनिक आंकड़े इस बात पर निर्भर करते हैं।

एक जीवंत संस्कृति, कहां होता है इसका उगम

अजय

क्या आपने पश्मीना के बारे में सुना है? हो सकता है आपने सुना हो कि ये दुनिया का सबसे मुलायम धागा है। सत्रहवीं शताब्दी में पश्मीना

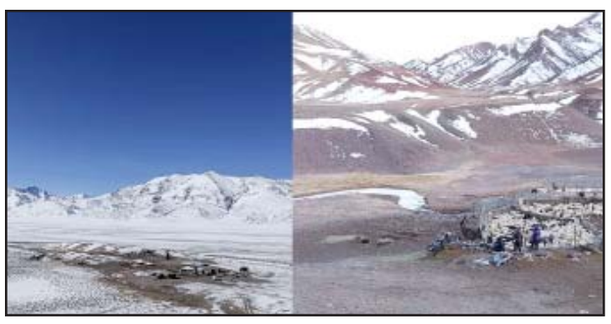

से बने कश्मीरी शॉल पश्चिमी देशो में बहुत मशहूर हुए। आज भी पश्मीना दुनिया भर में कश्मीर और भारत की पहचान है। दरअसल, इसी वजह से पश्मीना को दुनिया भर में 'कैशमेयर' के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर मैं आप से पूछूं कि पश्मीना कहां बनता है तब आप क्या कहोगे? कश्मीर में? चीन से आता है? या कहीं और से? चलिए आज हम आप को ले चलते हैं उन ऊंची पहाड़ी वादियों में जहां पश्मीना का उगम होता है। उत्तरी तिब्बत एक बहुत बड़ा पहाड़ी मैदानी इलाका है जिसे चांगथांग के नाम से जाना जाता है। चांगथांग– चांग यानि उत्तर और थांग यानि मैदान इन दो तिब्बती शब्दों का जोड़ है। चांगथांग लगभग 25 लाख वर्ग कि.मी. इलाके में फैला है जिसमें से लगभाग 17,000 वर्ग कि.मी. हिस्सा लद्दाख के पूर्वी भाग में पड़ता है। चांगथांग में रहनेवाले लोगों को चांगपा के नाम से जाना जाता है और इनके जीवन बसर करने का तरीका बिलकुल निराला है। चांगथांग का अधिक्तम् हिस्सा 4,000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर है। क्या आप सोच सकते हैं कि 4,000 मीटर पर जीने में किस तरह की दिक्कतें आती होगी? अव्वल तो यहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, खास कर जादे में जब तपमान –35C तक गिर जाता है। चांगपा समुदाय जिन स्थानों में बस्ते हैं वो अति दुर्गम है। तो यहाँ कोई कैसे और क्यों जीता है? चांगपा सदियो से पशुपालन करते आ रहे हैं। क्योंकि यहां के हालात कृषि के योग्य नहीं हैं, पशुपालन उनके पास एक मात्रा विकल्प है। और क्योंकि इन ऊंचाइयों में घास की उपज सीमित मात्रा में होती है चांगपा समुदाय घुमंतू जीवन बसर करते हैं। लद्दाख में चांगपा समुदाय अलग–अलग घाटियों में रहते हैं। हर बड़ी घाटी में रहने वाले समुदाय को एक गांव की तरह देखा जा सकता है। लद्दाख चांगथांग में कुल 22 समुदाय हैं और हर समुदाय में 20 से 300 परिवार हैं। हर परिवार में 5–6 लोग होते हैं और सारा परिवार रेबो में रहता हैं। रेबो एक खास प्रकार का तंबू है जिसे याक के बाल से बनाया जाता था और ये सर्दी–गर्मी दोनों में काम देता है। चांगपा मानते हैं कि सर्दियों में रेबो गरम रहता है और गर्मियों में ठंडा। जब एक घाटी से दूसरी घाटी जाने का समय आता है तब पूरा परिवार अपना रेबो समेट कर अगले पड़ाव के लिए चल देते हैं। हर पड़ाव पर गांव 2 से 3 महीने बिताता है। इस तरह पूरा गांव साल भर पूर्वनिर्धारित घाटियों में समय बिताता है। घर के हर सदस्य को काम में हाथ जुटाना पड़ता है। पशुओं को सुबह पहाड़ों में ले जाना और शाम होते होते लौटना दिन का सब से बड़ा काम है। सर्दीयों के लिए गोबर चुगने का काम भी साल भर करना पड़ता है। ये सब और इसके अलावा सभी घरेलू काम परिवार के महिलाएं और पुरुष मिलकर करते हैं। एक घाटी से दूसरी घाटी जाने के निर्णय गांव के मुखिया – जिसे गोबा कहते हैं – द्वार किया जाता है। हर गांव अपना गोबा एक से तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त कर्ता है। गोबा की जिम्मेदारी हर परिवार को निभानी पड़ती है। गोबा का काम मुश्किल है और इसे निशुल्क सेवा के तौर पर किया जाता है। याद रहे कि गोबा, पंचायत प्रधान से अलग है और ये रिवाज चांगपा समाज में कई सदियों से पाला जा रहा है। गांव के बड़े फैसलो में गोबा गांव के लोगों की राय लेते हैं। चांगपा समुदायों के लिए उनके जानवर सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनमें याक, घोड़े, गधे और भेड़–बकरियां शामिल हैं। और रही बात पश्मीन की, तो वो इन्हीं बकरियों के बाल से बनता है। चांगथांग में पाली जाने वाली बकरियां सर्दियां में खास किसम के बाल उगते हैं जिससे वो अत्यध्िक ठंड बर्दाश्त कर पाती हैं। हर साल गर्मियों में बकरियों के बाल झड़ने लगते हैं जिन्हें चांगपा कंघी करके निकाल लेते हैं। हर साल जून–जुलाई के महीनों में चंपगा पश्मीना के बाल निकालने के काम में व्यस्त हो जाते हैं। इस चारागाही समुदाय के लिए ये साल का सब से महत्वपूर्ण फसल है। इन बालों को व्यापारी 3,000 रुपये प्रति किलो के दाम से खरीद लेते हैं। इन्ही बालों को साफ करके पश्मीना धागे बनने तक इनकी कीमत 16,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है। पश्मीना धागों से शाल बुनाई करने का हुनर कश्मीर घाटी में सदियों से रहा है। चांगथांग और कश्मीर का ये नाता कम से कम 400 साल पुराना है। अधिकार लोग पश्मीना को कश्मीर के साथ जोड़ते हैं पर चांगथांग के बारे में कम लोगों को पता है। भारत के कई जनजाति समुदायों की तरह चांगपा जमीन से जुड़े हैं और पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर हैं। चांगपा समाज का सारा संगठन उन्हें मुश्किल हालात से संघर्ष करने में मददगार रहा है। पश्मीना इन्हीं समुदायों के मंथन से बनता है। पश्मीना सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि हजारों साल से चली आ रही एक जीवंत संस्कृति है जिसे चांगथांग के लोग आज भी जी रहे हैं।

हम हिमालय को बचाने में बहुत कंजूस

ललित

अगर आप इस कॉलम का नाम शाब्दिक रूप से लेना चाहते हैं, तो आप कितनी दूर तक जाना चाहेंगे? सिर्फ अजीबोगरीब विचार सोचने के बजाय, क्या आप सबसे कठिन हाइकिंग पथ चुनेंगे, जो खतरे और रोमांच से भरा हो, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका सामना यथासंभव कम इंसानों से हो, जिससे आपकी खघ्तरनाक यात्रा एक आत्म–अन्वेषण बन जाए जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता?और अगर आपको ऐसा करना पड़े, तो इस ग्रह पर आपको एकांत और अनुभवहीन रोमांच दोनों कहाँ मिलेंगे?मैं कल्पना करता हूँ कि समुद्र के नीचे। वे कहते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर के अंतरिक्ष से भी ज्यादा अज्ञात। दूरबीनें, परिक्रमा से लेकर रेडियो तक, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में 13 बिलियन साल से ज्यादा पुराने समय को देख सकती हैं। लेकिन समुद्र की गहरी गहराई? रहस्य और राक्षस छिपे हुए हैं। लेकिन वास्तव में, मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ नहीं जाएँगे। क्योंकि महासागर पहले से ही बहुत ज्यादा कचरे से भरे हुए हैं। हम इंसानों ने किसी समय यह तय किया कि चूँकि हमने जमीन को काफी प्रदूषित कर दिया है, इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपना कचरा समुद्र में फेंक दें। हम भूल गए कि ग्रह गोलाकार है, और जो घूमता है, वही वापस आता है। इसलिए पानी कचरे से भरा है, जिसमें फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलों से लेकर समुद्री जीवों द्वारा खाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक तक शामिल हैं। जिनमें से कुछ हम खाते हैं। जो शायद हम ईमानदारी से इसके लायक हैं। और जैसा कि हम जानते हैं – या हमें पता होना चाहिए – जैसे–जैसे लोग इस ग्रह पर अनदेखी भूमि की गहराई में खोज करते हैं, हम अपने पीछे ऐसे हिस्से छोड़ जाते हैं जो वाकई घिनौने होते हैं। सबसे ऊंचे भू–पहाड़ पर इंसानों के मल–मूत्र और मलबा भरा पड़ा है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग इस साहसिक कार्य के लिए साइन अप कर रहे हैं और अपनी बकेट लिस्ट में टिक कर रहे हैं। हममें से कई लोगों के मरने के बाद भी यह कचरा लंबे समय तक बना रहेगा।हर साल, कम इस्तेमाल किए जाने वाले और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों पर मानवीय क्षति के अधिक सबूत मिलते हैं। धार्मिक पर्यटन में इंसानों के लिए पहाड़ों और जंगलों को नष्ट करना जरूरी है। जो कभी भक्ति के प्रमाण के रूप में व्यक्तिगत बलिदान की यात्रा थी, वह अब एक शानदार छुट्टी बन गई है। यात्री के लिए बड़ी कीमत पर और जमीन, हवा, पर्यावरण और उन लोगों के लिए सबसे बुरी कीमत पर जो किसी और की खुशी के लिए नष्ट किए गए क्षेत्रों में रह रहे हैं। कभी–कभी, दुनिया के घ्नेताघ् किसी स्वास्थ्यप्रद रिसॉर्ट में मिलते हैं और ग्रह के भविष्य पर चर्चा करते हैं और बड़े–बड़े वादे करते हैं। उनमें से अधिकांश पूरे नहीं होते और जो होते भी हैं, वे शायद ही कभी न्यूनतम से अधिक होते हैं। फिर मानव जाति द्वारा किए गए विनाश को सुविधा की कीमत के साथ संतुलित किया जाता है। मैं जल्द ही मरने वाला हूँ, इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के साथ क्या होता है, इसकी परवाह कौन करता है और उन्होंने अतीत में हमसे कहीं ज्यादा बुरा किया है, इसलिए हम वर्तमान में उनके जितना क्यों भुगतें मिलते हैं। दोनों में से कोई भी तर्क स्पष्ट रूप से विवादास्पद नहीं है और इसलिए, दोनों तर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका प्रभाव और अधिक विनाशकारी है। सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला रास्ता विकास का है। हमें इसकी और अधिक आवश्यकता है। हमें प्रगति करनी चाहिए और प्रगति का मतलब बुनियादी ढाँचा है। हालाँकि, प्रगति का मतलब मौजूदा बुनियादी ढाँचे का रखरखाव नहीं है। संभवतः यह सामान्य बात नहीं है। और इसलिए, मानसून की शुरुआत के साथ ही सड़कें, पुल और हवाई अड्डे ढह गए हैं। कुछ हताहतों के नाम तो यही हैं।ज्यादा बुनियादी ढाँचा बनाने और ज्यादा प्रगति और विकास के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का और भी अध्िक विनाश होना चाहिए। इसलिए हम विदेश यात्रा करते हैं और राष्ट्रों के समुदाय से अपने जंगलों को बनाए रखने का वादा करते हैं और कार्बन पृथक्करण में अपने अपार योगदान के लिए खुद की पीठ थपथपाते हैं। फिर हम भारत वापस आते हैं और वन भूमि के बड़े हिस्से पर हस्ताक्षर करते हैं और नाजुक पहाड़ी ढलानों पर धार्मिक पर्यटन के लिए सड़कें बनाने का फैसला करते हैं। इस प्रकार, जैसे–जैसे हमारे आस–पास मानव निर्मित बुनियादी ढाँचा ढहता है, मानव निर्मित विकास पहाड़ों को गिराता है और जंगलों को साफ करने से वैश्विक और स्थानीय तापमान बढ़ता है। यह केवल अगली गर्मी की लहर पर ही महसूस किया जाएगा, इसलिए यह वास्तव में मायने नहीं रखता है, है न? उम्मीद है कि तब तक हर कोई भूल जाएगा जैसा कि वे हमेशा करते हैं। यहाँ हिमालयी राज्य उत्तराखंड में, हमें दो महीनों की छोटी अवधि में मौसम की चरम स्थितियों का अनुभव करने का सौभाग्य मिला है। हम दुर्बल करने वाली गर्मी की लहरों से विनाशकारी भूस्खलन और बाढ़ तक पहुँच गए हैं। यानी, लोगों को एक आपदा से उबरने के लिए मुश्किल से ही समय मिला है कि वे अगली आपदा में फंस जाएँ। ग्रह को इसकी चेतावनी दी गई थी। कि हम टिपिंग पॉइंट के करीब थे और जलवायु परिवर्तन कठोर स्थानीय मौसम की घटनाएँ ला सकता है। हमने सुना, लेकिन हमने नहीं सुना।जब आप पर्यावरण की बात करते हैं तो यहाँ दो तर्क दिए जाते हैं। एक जो मैं सबसे ज्यादा सुनता हूँ वो ये है कि लोगों को घर चाहिए और स्थानीय लोगों को सड़क चाहिए। ये दोनों ही बातें सच हैं। लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ कोई भी "विकास" स्थानीय लोगों के लिए नहीं है। अगर कोई सरकार स्थानीय लोगों की परवाह करती, तो जोशीमठ शहर के नजदीक एक बड़ी सड़क नहीं बनाई जाती, जो पूरी तरह से ढहने के कगार पर है। न ही हाइड्रोपावर प्लांट बनाए जाते जहाँ वे आस–पास रहने वालों की जान को खतरे में डालते।दूसरा ये कि पश्चिमी दुनिया विकसित हो चुकी है, तो हम क्यों नहीं? दुख की बात है कि ग्रह इस विकास और उस विकास के बीच अंतर करता है। आपको बस जंगली आग और तूफानों की तबाही पर ध्यान देने की जरूरत है उत्तरी अमेरिका को इसे महसूस करने के लिए।मेरी दो पसंदीदा फिल्में हैं द डे आफ्टर टुमॉरो और डोंट लुक अप।

क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों रिक्तपदों हेतु निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2024 द्वारा क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानोंध्पदों, जो मा० न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है।

उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेटध्जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), जौनपुर, जनपद के रिक्त क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों का उप निर्वाचन, जो मा० न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश देता हूँ। नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम 22 जुलाई 2024 को पूर्वान्ह् 10.00 बजे से अपरान्ह् 04 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 23 जुलाई पूर्वान्ह् 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेना 24 जुलाई, 2024 पूर्वान्ह् 10.00 बजे अपरान्ह् 03.00 बजे, प्रतीक आवंटन 24 जुलाई 2024 अपरान्ह् 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, मतदान 06 अगस्त 2024 प्रातः 07.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक, मतगणना 08 अगस्त 2024 प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों के रिक्त स्थानोंध्पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा 18 जुलाई, 2024 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार कराया जायेगा और गाँवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत होने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जाएगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। उपर्युक्त उप निर्वाचन में नाम निर्देशन पत्रों का विक्रय, नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिए जिला मुख्यालय पर होगा। सभी मतों की गणना क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। सदस्य क्षेत्र पंचायत के स्थानोंध्पदों का निर्वाचन परिणाम क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा सदस्य जिला पंचायत के स्थानोंध्पदों का निर्वाचन परिणाम जिला मुख्यालय पर घोषित किया जाएगा। उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए ऑनलाइन वेबसाइट की तिथि जारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिला विद्यालय निरीक्षक ने अवगत कराया है कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक उ०प्र० शिक्षा सामान्य (2) अनुभाग प्रयागराज के द्वारा प्रदेश के राजकीयध अशासकीय माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय तथा वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक से "राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए ऑनलाइन वेबसाइट https://nationalawardstoteachers.education.gov.in पर संशोधित आवेदन तिथि 16 जुलाई 2024 से 18 जुलाई 2024 तक रजिस्ट्रेशन करने हेतु निर्धारित करते हुए 21 जुलाई 2024 तक अन्तिम रूप से आवेदन दाखिल किये जाने का निर्देश दिया गया है। जनपद–जौनपुर के इच्छुक/अर्ह आवेदक उक्त निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते है जिसकी विस्तृत सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है।

दिनांक 19 जुलाई को प्रातः 10:00 बजे से क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लालबाग लखनऊ परिसर में रोजगार मेला किया जाएगा आयोजित

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। सहायक निदेशक (सेवा0) लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने जानकारी देते हुए बताया है कि युवाओंध्युवतियों को रोजगारध स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाना तथा हर हाथ को काम सरकार की प्राथमिकताओं में है। सरकार के संकल्प पत्र में युवाओं को रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। इसी क्रम में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लखनऊ द्वारा दिनांक 19.07.2024 को प्रातः 10:00 बजे से एक रोजगार मेले का आयोजन क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लालबाग, लखनऊ परिसर में किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि उक्त मेले में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी रोजगार संगम पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर पंजीकृत होकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा अपनी सी0वी0 की प्रतियों एवं मूल शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के साथ अभ्यर्थी सीधे प्रतिभाग कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को किसी भी स्तर पर कोई शुल्क नहीं देना है। रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण एवं अन्य किसी असुविधा की स्थिति में टोल फ्री नम्बर 155330 पर सम्पर्क कर सकते है। इस मेलें में प्रतिभाग करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट है। इस हेतु किसी भी प्रकार का मार्गव्यय आदि देय नहीं होगा। यह मेला पूर्णतः निःशुल्क है।

पिछड़ी जाति के बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए ओ लेवल एवं सी0 सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना आनलाइन की जा रही है संचालित

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अभिषेक कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछड़ी जाति के बेरोजगार युवकध्युवतियों के लिए वर्ष 2024–25 हेतु ओ लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना ऑनलाइन संचालित की जा रही है। वर्ष 2024–25 में इस योजना के अन्तर्गत इच्छुक अन्य पिछड़े वर्ग के वेरोजगार युवक/युवतियों द्वारा ओ लेवल एवं सी0 सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु जनपद की चयनित प्रशिक्षणदायी संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0 की विभागीय बेवसाइट obc computer training.upsdc.gov.in पर निर्धारित दिनांकः 11 जुलाई, 2024 से 05 अगस्त, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस हेतु दिशा–निर्देशध्समय सारिणी बेवसाइट पर भी प्रदर्शित कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के उपरान्त छात्र द्वारा ऑनलाइन भरे गये आवेदन–पत्र की प्रति डाउनलोड कर प्रिन्टआउट प्राप्त कर हस्ताक्षरित करते हुए आवेदन में अंकित समस्त वांछित स्व प्रमाणित अभिलेखों सहित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, इन्दिरानगर विकास भवन, द्वितीय तल में निर्धारित अन्तिम तिथि 05 अगस्त, 2024 की सायं 05 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा कर देगें। निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र की हार्डकापी कार्यालय में प्राप्त न होने की स्थिति में छात्रध्छात्रा का आवेदन–पत्र अपूर्ण माना जायेगा तथा छात्र का प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना की पात्रता के लिए प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट अनिवार्य है, आवेदक की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, आवेदक बेरोजगार हो तथा वह विभाग से अन्य कोई लाभ न ले रहा हो एवं आवेदक के माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रू0 1,00,000.00 से अधिक न हो।

न्यायालय पेशी पर जाते समय पुलिस अभिरक्षा से आरोपी फरार, पुलिस की सक्रियता से पाच मिनट बाद गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । लाइन बाजार थाना क्षेत्र के दीवानी न्यायालय में मंगलवार दोपहर उसे समय हड़कंप मच गया जब लाकअप से कोर्ट पर पेशी पर जाते हुए आरोपी रोहित बिंद पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। वो स्पेशल जज एस सी एस टी कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था। आरोपी के भक्ति ही पुलिस के हाथ–पाव फूल गए हालांकि पुलिस ने सक्रियता से तत्काल न्यायालय के बाहर कुछ दूरी पर दौड़ा कर उसे पकड़ लिया। और न्यायालय में पेश किया।

बता दें कि शाहगंज थाना क्षेत्र के सुरिस गांव निवासी रोहित बिंद पुत्र राम वचन को 6 जून 2024 को पुलिस ने गिरफ्तार कियाथा तब से ये जिला कारागार में निरुद्ध है। उसके ऊपर गैंगरेप का आरोप लगा था । पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया है। मंगलवार को करीब दो बजे पेशी पर जाते समय वह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया पुलिस ने सक्रियता से पाच मिनट के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर दिया। इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं न्यायालय में कैदियों की सुरक्षा में तैनात किसी भी अधिकारी द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया है।

मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में सदर सांसद का बयान यह जीत मतदाता और कार्यकर्ताओं को समर्पित

हरदोई(अंबरीष कुमार सक्सेना) लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा ने मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया। जिला भाजपा कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम के तहत

हरदोई विधानसभा के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए मंगलवार को जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन की अध्यक्षता में सदर सांसद जय प्रकाश एवं सदर लोकसभा संयोजक प्रीतेश दीक्षित ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी मतदाताओं एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बोलते हुए सदर सांसद जय प्रकाश ने कहा कि विपक्ष की झूठी और भ्रामक राजनीति के कारण जनता बहक गई जिस कारण भाजपा को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई। असल में जमीन पर काम भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने किया। विरोध की बयार में बहके मतदाताओं भाजपा के पक्ष में कर बूथ तक लेकर आया। सांसद ने महिलाओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने देखा है कि कैसे हमारी बहनें और माताओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा के पक्ष में मतदान किया। सांसद ने कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर बोलते हुए कहा कि राजनैतिक और चुनाव प्रचार की बंदिशों और व्यवस्तताओं के कारण वह बहुत से लोगों से मिलने में चूक गए जिस कारण उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ा और उन्हें इस का एहसास है। सांसद ने आश्वस्त करते हुए कहा कि इस बार नेताओं से ज्यादा समय वह अपने कार्यकर्ता और अपनी जनता को देंगे। केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ जनता को मिले इसके लिए वह पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। हरदोई के विकास में अब कोई अड़चन आने नहीं दी जाएगी। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने कहा कि हरदोई विधानसभा के कर्मठ कार्यकर्ताओं और भाजपा के पक्ष में मतदान करने वाले मतदाताओं को नमन करता हूं जिन्होंने विरोध के भ्रामक प्रचार को तोड़ने का काम किया। जो लोग संविधान बदलने का झूठा आरोप भाजपा पर लगा रहे है वह जरा पहले अपने जमीर को झकझोरें। समाजवादी क्या वह दिन भूल गए जब कांग्रेस ने संविधान बदलकर आपात काल लगाया था। उसी अपातकाल में हजारों नेताओं और बुद्धिजीवियों को कांग्रेस की मुखालफत करने के लिए जेल में डाल दिया गया था। आज वही कांग्रेस एक वर्ग को लुभाने के लिए पूरे देश के हिंदुओं का अपमान करती घूम रही है। हिंदू हिंसक नहीं हिंदू रक्षक है। इसीलिए जनता ने कांग्रेस के झूठे षड्यंत्र को पूरी तरह से नकार कर करारा जवाब दिया और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में देश का नेतृत्व सौंप दिया।

संचालन विधानसभा प्रभारी अविनाश मिश्रा ने किया

कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व जिला अध्यक्ष राम बहादुर सिंह, राजीव रंजन मिश्र, श्रीकृष्ण शास्त्री, जिला उपाध्यक्ष प्रीतेश दीक्षित, संजय सिंह गुड्डू, जिला महामंत्री ओम वर्मा, अनुराग मिश्र क्रय विक्रय अध्यक्ष सुशील अवस्थी छोटे महाराज ने भी सभा को संबोधित किया। प्रमुख रूप से जिला महामंत्री सत्येंद्र राजपूत जिला मंत्री अविनाश पांडे अजय शुक्ला जिला मीडिया प्रभारी गांगेश पाठक विपिन सिंह गौर युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष आकाश सिंह आईआईटी प्रमुख सौरभ सिंह गौर सह मीडिया प्रभारी परेश गुप्ता सत्यम शुक्ला महिला मोर्चा महामंत्री रीना गुप्ता अनुराधा मिश्रा मुकुल सिंह आशा चेतना शुक्ला पारिषा तिवारी मंडल अध्यक्ष अजीत उपाध्यक्ष श्याम सिंह राम प्रताप सिंह एवं देश दीपक दीक्षित सहित तमाम कार्यकर्ता एवं आमजन मौजूद रहे।

तिलहर की विधायिका सलोना कुशवाहा ने क्षेत्र में आई भयंकर बाढ़ से हुई हानि एवं पीड़ितों की समस्याओं के निराकरण से संबंधित जिलाधिकारी को सौंपा पत्र'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' मंगलवार को तिलहर विधायक सलोना कुशवाहा ने जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि 133 विधानसभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम चिती भोजी, अजमाबाद, बिहारीपुर जिकरीपुर, मोहनापुर, धमनपुर गौटिया, त्रिलोकपुर, प्रहलादपुर, कबीरचक, चौढेरा चौढेरी बधुईअक्का, पकड़िया, चकुलिया, बरूआर, बरहा मुहब्बतपुर, रानी खिरिया, ढकिया रघा, धमनपुर, मरक्का गौटिया चमरूआ, बरौरा, सकतिया, विक्रमपुर चकौरा, भर्री बसन्तपुर, सहजादपुर, बन्डिया, मुडिया, तिदुलिया, साधन वाली गौटिया, ऊन व तालगांव चक्रमली रतुली आदि ग्रामों में दिनांक 10 जुलाई की रात्रि में आई भयंकर बाढ़ के कारण स्थिति अत्यन्त खराब है। बाढ़ के कारण खरीफ की फसलें जलमग्न हो गयी है। मवेशीध पशुओं के लिए चारे का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। जल भराव के कारण उपरोक्त ग्रामों में संक्रमणीय रोग फैलने की प्रबल सम्भावना है। ग्राम वासियों की सम्पत्तियों को भी भारी नुकसान हुआ है। साथ ही आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि रटा नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण रोड पर कटाव हो गया है जिससे तहसील आने जाने में क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

जो अत्यंत संकट का विषय है। जिसको आवागमन हेतु ठोस व्यवस्था कराये जाने की अत्यंत आवश्यकता है। वही मेरी विधानसभा क्षेत्र के उपरोक्त ग्रामों के ग्रामवासियों को राहत सामग्री भोजन, दवायें, मवेशीध पशुओं के लिए चारे की तथा बाढ़ से बचाव हेतु व्यवस्था अतिशीघ्र करवाये जाने की जनहित में अत्यंत आवश्यकता है।

अयोध्या का विकास करना प्रमुख प्राथमिकता – नवागत डीएम चन्द्र विजय सिंह

(डॉ अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। राम नगरी का चहुंमुखी विकास करना हमारी प्रमुख प्राथमिकता रहेगी।इसके अलावा राम मंदिर व अन्य मेलों व पर्वों में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो इसके लिए यहां के अधिकारियों व स्थानीय लोगों के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित किया जाएगा।यह बातें मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में नवागत जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कही।इस मौके पर उन्होंने अपने को भाग्यशाली बताते हुए कहा कि आज हमे अयोध्या धाम का सेवा करने का मौका शासन द्वारा मिल रहा है।उन्होंने कहा कि हमारी भरसक प्रयास रहेगा कि हम अयोध्या के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।उन्होंने कहा कि राम नगरी मे हजारो लाखो की संख्या में श्रद्धालु आते हैं।हम सभी का यही प्रयास रहे कि हम सभी उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराने का काम करे।जिससे यहां पर आने वाले श्रद्धालु यहां से संतुष्ट होकर अयोध्या का गुणगान अपने अपने गन्तव्य स्थानों पर जाकर करे।उन्होंने बताया कि मेरी पूरी कोशिश होगी जो यहां के निवासी हैं और जो आने वाले श्रद्धालु हैं। उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो।उनकी समस्याओं का गुणवत्ता पूर्वक समाधान किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जिले में जहां भी सुधार की आवश्यकता है वहां सुधार किया जाएगा और बेहतर तरीके से जनता के बीच इन सब चीजों को लाया जाएगा। सफाई,चिकित्सा और शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में भी और बेहतर कर सके इसका प्रयास होगा। उन्होंने बताया कि उनको शासन ने जो जिम्मेदारियां सौंपी है और जनता की जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे।आगामी सावन झूला मेला, व कावड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रहा है इसके लिए प्रशासन व पुलिस की टीम की कोआर्डिनेशन मीटिंग हो चुकी है। इन सभी पर्वों को सकुशल सम्पन्न कराने के लिये उन्होंने अधिकारियों संग बैठक कर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह सभी अधिकारी व कर्मी बनाए रखे।बताते चलें कि वर्ष 2012 बैंच के आईएएस अधिकारी नवागत डीएम चंद्र विजय सिंह इसके पहले मध्यांचल विद्युत वितरण खण्ड के एमडी, डीएम फिरोजाबाद,सीडीओ झांसी, सहित अन्य वह आज शाम या मंगलवार की सुबह कार्यभार संभाल सकते हैं। कार्यभार संभालने के साथ उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन पूजन कर दर्शन पूजन किया।

पुरानी पेशन योजना की बहाली के चलाये जा रहे आन्दोलन

मृत्युंजय प्रताप सिंह

लखनऊ। आज प्रदेश के जनपद मुख्यालयों सहित राजधानी लखनऊ में मा० प्रधानमंत्री जी, मा० वित्तमंत्री जी भारत सरकार एवं मा० मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपेने के लिए कर्मचारी प्रेरणा स्थल

पर बड़ी संख्या में कर्मचारी एंव शिक्षक एकत्र हुए। अवगत कराना है कि पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मच केन्द्रीय कर्मचारियों (रेलवे, सिविल डिफेंस, पोस्टल, इनकम टैक्स आदि), राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों के संयुक्त मंच द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियो को 01 जनवरी, 2004 से व उ०प्र० के कर्मचारियों व शिक्षकों को 01 अप्रैल, 2005 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर पूर्वपरिभाषित सुनिश्चित लाभ वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मॉग की जा रही है। समेकित मंच के आवहन पर देशध्प्रदेश भर के राजकीय कर्मचारीध शिक्षक विगत एक वर्ष से लगातार चरणबद्ध आन्दोलन पर थे। अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्र व राज्य कर्मचारियोंधशिक्षकों द्वारा चलाये जाने वाले आन्दोलन की श्रंखला में 07 जनवरी, 2023 को पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच का गठन किया गया तथा दिनांक 21 जनवरी, 2023 को प्यारे लाल भवन सभागार, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर सर्वसम्मति से वृहद आन्दोलन चलाये जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 10 फरवरी 2023 से दिनांक 20 फरवरी, 2023 तक महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली हेतु करोड़ों की संख्या में ऑनलाइन पिटीशन कर्मचारियों द्वारा भेजी गई। दिनांक 21 फरवरी, 2023 को केन्द्र व राज्य सरकार के सभी कार्यालयों पर रैली निकाली गई। दिनांक 21 मार्च, 2023 को समस्त जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना/प्रदर्शन कर ज्ञापन प्रेषित किये गये, तथा दिनांक 22 मार्च 2023 से दिनांक 21 अप्रैल, 2023 तक कार्यालयों पर गेट मीटिंग कर कर्मचारियों में जनजागरण किया गया। दिनांक 21 मई, 2023 को सभी जनपदों में कर्मचारियों व उनके परिवारजनों द्वारा जनपद मुख्यालयों पर विशाल मशाल जुलूश का आयोजन कर पुरानी पेंशन बहाली हेतु आवाज बुलंद की गई। संयुक्त मंच (छप्ष्।) की केन्द्रीय कार्यकारिणी के निर्णयानुसार दिनांक 27 जून, 2023 को प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश व्यापी रैली किये जाने का निर्णय लिया गया। रैली की सफलता हेतु राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ०प्र० एवं मंच के घटक संगठनों द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में पेंशन रथ चला कर जनजागरण किया गया। प्रथम चरण में पेंशन रथ दिनांक 16 मई, को कानपुर नगर से प्रारम्भ होकर बुन्देल खण्ड व पूर्वी उ०प्र० से गुजरते हुये दिनांक 14 जून, 2023 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्पन्न हुई।

समाज, सरकार और बाजार के माध्यम से नागर समाज को सशक्त करना होगा – संदीप श्रीवास्तव

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। समाज, सरकार और बाजार दर्शन का मानना है कि सतत विकास के लिए समाज, सरकार और बाजार के बीच सामंजस्य आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में राज्य के पैमाने और विविधता को देखते हुए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ रहा है, जो इसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। लेकिन इस क्षमता को मूर्त विकास में बदलने के लिए समाज के सभी क्षेत्रों से ठोस प्रयास आवश्यक हैं। ये बात गैर सरकारी संगठन शोहरतगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी के सचिव संदीप श्रीवास्तव ने होटल रनबीर्स में प्रेस वार्ता के दौरान कही। संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शोहरतगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वार्षिकोत्सव श्अभ्युदयश का आयोजन आगामी 19 जुलाई को होटल रेगनेंट निरालानगर में किया जा रहा है। इस बार वार्षिकोत्सव का विषय है, समाज, सरकार और बाजार से नागर समाज को सशक्त बनाना। संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 19 जुलाई 2024 को वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सीनियर आईएएस डॉ. हीरालाल को आमंत्रित किया गया है। संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस वर्ष का अभ्युदय नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश के विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित है। वार्षिकोत्सव में इस विषय पर चर्चा होगी कि कैसे समाज, सरकार और बाजार नागरिक समाज को सशक्त बना सकते हैं। अभ्युदयश वार्षिकोत्सव का उद्देश्य विकास में नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना, नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए रणनीतियों का अन्वेषण करना, सहयोग के अवसरों की पहचान करना है। संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि वार्षिकोत्सव में इन बिंदुओं पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में नागरिक समाज के लिए चुनौतियाँ और अवसर नागरिक समाज और अन्य क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों प्रभावी नागरिक समाज कार्य के लिए क्षमता और संसाधन निर्माण E, INNOVATE IMPACT नागरिक समाज को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का लाभ उठाना।

विकसित की जा रही थी अवैध कालोनी, 50 प्लाटों की नींव की गई ध्वस्त

मैनपुरी, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना नक्शा पास कराए की जा रही प्लॉटिंग को बुलडोजर से प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया है। एसडीएम ने कहा कि शहर में अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया जा रहा है। इनके विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है। पहले दिन सोमवार को महमूद नगर में 50 प्लाटों की नींव को ध्वस्त कराया गया। शहर में कई क्षेत्रों में अकृषक भूमि पर बिना अनुमति के और बिना नक्शा पास कराए ही अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है। जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने एसडीएम सदर को अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। एसडीएम अभिषेक कुमार ने अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अभियान के पहले दिन उपजिलाधिकारी के निर्देशन में राजस्व टीम शहर के मोहल्ला महमूद नगर नई बस्ती पहुंची। यहां अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। टीम ने बुलडोजर चलवाकर करीब 50 प्लॉटों में भरी गई नींव को ध्वस्त कराया। कुछ कॉलोनाइजर्स पहुंचे और विरोध करने का प्रयास किया लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। प्लाटों की नींव को पूरी तहर ध्वस्त करते हुए चेतावनी दी कि बिना आबादी घोषित किसी प्रकार से बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग का कार्य न किया जाए। टीम में तहसीलदार मैनपुरी विशाल यादव, नायब तहसीलदार शौर्य राठौर, लेखपाल सदर पुष्पेंद्र सिंह चौहान, ब्रजेश राठौड़ मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान शहर कोतवाली पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त नगर पालिका की टीम भी मौके पर मौजूद रही। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में बिना आबादी घोषित किसी भी जमीन पर प्लॉटिंग नहीं होने दी जाएगी।

शिक्षकों का विरोध जारी, केवल पांच ने लगाई हाजिरी

शामली, संवाददाता। शिक्षा अधिकारियों के समझाने के बावजूद भी शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। शनिवार को केवल पांच शिक्षकों ने ही ऑनलाइन हाजिरी लगाई। वहीं शिक्षक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में सांसद को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी दिया। सोमवार को कलक्ट्रेट में शिक्षक ज्ञापन देंगे। जनपद के परिषदीय स्कूलों में छठवें दिन भी ऑनलाइन हाजिरी का विरोध रहा। अधिकतर स्कूलों में काली पट्टी बांधकर ही शिक्षण कार्य किया गया। शिक्षा अधिकारी रोज शिक्षकों को स्कूल में पहुंचकर समझाने का प्रयास कर रहे है, इसके बावजूद भी संख्या बढ़ने के बजाय आए दिन घटते जा रहे है। शनिवार को भी पहले दिन के मुकाबले दो शिक्षक कम हो गए। 2993 में से केवल 5 शिक्षकों ने ही हाजिरी लगाई। संगठन के दबाव में आए दिन संख्या घटती जा रही है। शनिवार को भी शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। खंड शिक्षा अधिकारियों ने स्कूलों में घूमकर शिक्षकों को समझाया। अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक मिड–डे मील की रिपोर्ट तो ऑनलाइन भेज रहे है, लगभग 50 स्कूलों में शिक्षक बच्चों की हाजिरी भी ऑनलाइन लगा रहे है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही जूनियर शिक्षक संघ के नेतृत्व में आदेश पंवार, सुनील पंवार ने शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी के विरोध में सांसद इकरा हसन से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। सांसद ने शिक्षकों की समस्याओं को बहुत ध्यान से सुना व आश्वासन दिया कि वह शिक्षकों के साथ है खड़ी है। इस मौके पर नितिन पंवार, रजत देशवाल ,बिलेंद्र चौहान, डॉक्टर राजीव वर्मा, शिवकुमार ,रोहित राणा, पीयूष कुछल, संजीव खोखर, अमित निर्वाल, कपिल, अमित, दीपक वर्मा, अमित खैवाल आदि मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

डीसीएम ने बाइक में मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा घायल हुआ

फतेहपुर, संवाददाता। फतेहपुर जिले में थरियांव थाना क्षेत्र के हसवा पुलिस चौकी के सामने बाइक सवार को डीसीएम ने पीछे से टक्कर मार दी। बाइक में पिता–पुत्र सवार थे। हादसे में पिता की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुत्र जीवन व मृत्यु के बीच झूल रहा है। कौशांबी जिले के मीरपुर मजरे अफजलपुर थाना पैंसा निवासी मान सिंह अपने पुत्र राजू (21) के साथ अपनी बेटी के यहां फतेहपुर जा रहे थे। रात करीब 11 बजे पुलिस चौकी के सामने पीछे से आ रहे डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पिता मान सिंह पुत्र केशव (45) की मौके पर ही मौत हो गई। चौकी प्रभारी बृजेश यादव टीम के साथ मौके पर पंहुचे। पुत्र राजू को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पंहुचाया। चौकी प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। उधर मृतक के भाई शिवकुमार को सूचना दी गई। सूचना पर घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने सुबह थाने पंहुचकर तहरीर दी है।

गर्भवती महिला फंदे पर लटकी मिली, लगाया हत्या का आरोप

हमीरपुर, संवाददाता। हमीरपुर में छह माह की गर्भवती की फंदा लगाकर जान दे दी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया। सूचना पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुस्करा थाना क्षेत्र के हुसैना गांव निवासी दिनेश प्रजापति ने बताया कि डेढ़ साल पहले उसकी शादी कुपरा निवासी विनीता (21) के साथ हुई थी। विनीता 6 माह से गर्भवती भी थी। रविवार रात को फंदा लगाकर जान दे दी। सुबह 4 बजे जब पानी बरसा तब जानकारी हो सकी। इसके बाद डायल–112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर नायब तहसीलदार सत्य प्रकाश, सब इंस्पेक्टर शिवम पांडे व जुबेर खान ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राठ भेज दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी दिलीप सिंह ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों के बयान लिए हैं। मौके पर पहुंची मां छोटी ने बताया कि उसकी बेटी को घसीट–घसीट कर पीटने के बाद हत्या की गई है। गर्भवती की मौत पर उसके भाइयों ने गालीगलौज के साथ जमकर हंगामा किया।

उधार सामान देने से मना किया तो कनपटी में लगा दिया तमंचा

बांदा, संवाददाता। दिव्यांग दुकानदार ने उधारी देने से मना किया तो शराबी ने तमंचा निकालकर उसकी कनपटी में लगा दिया। एसपी के आदेश पर आरोपी पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। बिसंडा थाना क्षेत्र के तेंदुरा गांव निवासी संतोष कुमार ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसका बेटा भूपेंद्र का दोनों पैरों से दिव्यांग है। अपने घर में परचून की दुकान रखकर परिवार भरण पोषण करता है। बताया कि गांव का ही राघव सिंह शराब के नशे में दुकान घुस आया और उधार सौदा मांगने लगा। मना करने पर उसने तमंचा निकालकर कनपटी में लगा दिया। बेटे के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर वाले दौड़े और मोहल्ले के तमाम लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने आरोपी राघव को तमंचा सहित पकड़कर कमरे में बंद कर लिया। ओरन चौकी पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के 48 घंटे बाद बिसंडा थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मारपीट एवं जानलेवा हमला करने की धाराओं पर रिपोर्ट दर्ज की है।

लूट की सूचना से मचा हड़कंप, लेनदेन का निकला मामला

मेरठ, संवाददाता। गढ़ी हसनपुर में रात को लूट की सूचना से हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंचीं और जांच की तो मामला लेनदेन का निकला। पुलिस ने झूठी लूट की सूचना देने वाले व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में मामले को निपटा दिया गया। चौसाना के गांव गढ़ी हसनपुर निवासी उमर खान चौसाना से आईसक्रीम बेचकर घर लौट रहा था। रात्रि करीब नौ बजे उमरखान ने पुलिस कंट्रोल रूम को छह हजार रुपये लूट की सूचना दी तो हड़कंप मच गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूछताछ की तो पता लगा गढ़ी हसनपुर के ही युवक ने लूटपाट को अंजाम दिया। पुलिस बताए गए आरोपी के घर पर पहुंची तो पता लगा कि 700 रुपये का उधार मांगने पर उमरखान ने झूठी लूट की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस उमरखान की ही शिकायत पर आरोपी युवक के भाई व पिता को लेकर पुलिस थाना झिंझाना पहुंची। रविवार सुबह को दोनों पक्षों के बीच फैसला होने पर उन्हें छोड़ दिया गया।

ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला और छह माह के मासूम की मौत हो गई

मेरठ, संवाददाता। मेरठ के परतापुर बाईपास पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला और उसके छह माह के मासूम बेटे की मौत हो गई। जबकि गंभीर घायल ससुर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गाजियाबाद में थाना निवाड़ी के गांव निवासी अन्नू पत्नी अर्जुन का कंकरखेड़ा में मायका है। अन्नू अपने छह माह के बेटे केशव और ससुर महेंद्र सिंह के साथ मायके आई थी। सोमवार सुबह तीनों बाइक पर वापस सारा गांव जा रहे थे। परतापुर बाईपास पर ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। ससुर महेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक सुरजीत को हिरासत में ले लिया है। दोनों शव मोर्चरी भिजवा दिए गए हैं।

बारिश न होने से गर्मी और उमस बढ़ी

शामली, संवाददाता। बारिश न होने से जिले का तापमान बढ़ रहा है। गर्मी व उमस से लोग बेहाल हैं। जिले के अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, जबकि न्यूनतम तापमान स्थिर बना रहा। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। आसमान में बादल छाते हैं, लेकिन बिन बरसे ही चले जाते हैं। रविवार सुबह से ही तेज धूप निकली और उमस बनी रही। दस बजे हल्के बादल कुछ समय के लिए छाये रहे, लेकिन उसके बाद फिर से तेज धूप निकली। तेज धूप निकलने से लोगों का गर्मी में हाल बुरा रहा। उमस बनने से लोग पसीने से तरबतर रहे। दोपहर में लोग धूप से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा लपेटकर जाते हुए दिखाई दिए।

पिछले 24 घंटे में जिले के तापमान की स्थिति देखें तो दिन का अधिकतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं रात के न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव न होकर 28 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा। ऊन क्षेत्र में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। दिनभर उमस भरी गर्मी से परेशान होने के बावजूद रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। रात के समय भी मौसम गर्म हो रहा है।

कानपुर में बनेंगे एडवांस तेजस लड़ाकू विमान के ब्रेक पैराशूट और हावर क्राफ्ट का बेस सिस्टम

कानपुर, संवाददाता। कानपुर की ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की इकाई आयुध पैराशूट निर्माणी (ओपीएफ) एडवांस तेजस लड़ाकू विमान के ब्रेक पैराशूट बनाएगी। निर्माणी ने इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। दिसंबर में लड़ाकू विमान में फिट करके इसका फील्ड ट्रायल शुरू किया जाएगा। इसके अलावा निर्माणी देश में पहली बार हावर क्राफ्ट का बेस सिस्टम बनाएगी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निर्माणी में अभी सुखोई, हॉक, मिराज, जगुआर, तेजस, मिग 21, मिग–29 लड़ाकू विमानों के ब्रेक और पायलट पैराशूट बनते हैं। ब्रेक पैराशूट की मदद से लड़ाकू विमानों को रनवे पर सुरक्षित उतारा जाता है। छोटे रनवे या समुद्री जंगी जहाजों में इन पैराशूटों की मदद से सुरक्षित लैडिंग होती है। देश में अब तेजस लड़ाकू विमान का आधुनिक संस्करण बनाया गया है। इस विमान का के ब्रेक पैराशूट का प्रोटोटाइप ओपीएफ में बनाया गया है। यूनिक्रॉस आकार के पैराशूट में कुल सात सब असेंबली हैं। इस पैराशूट की छतरी में इस्तेमाल किया जाने वाला मूल कपड़ा नायलॉन 66 प्रकार का है। करीब 10 किलो ग्राम भार वाले इस पैराशूट का प्रोटोटाइप बनाया गया है। यह पैराशूट सामान्य 285–300 किलोमीटर प्रति घंटा से आपात स्थिति में 340–350 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार होने पर विमान को रोकने में सक्षम होगा। इसे 10 साल तक या 50–55 बार इस्तेमाल में लाया जा सकेगा।

पानी में तैरता और जमीन पर चलता है हावर क्राफ्ट

निर्माणी में पहली बार हावर क्राफ्ट का बेस सिस्टम तैयार किया जाएगा। क्राफ्ट का बेस रबर का बना होता है। निर्माणी में सेना के लिए इन्फ्लेटेबल बोट, ब्रिज आदि का निर्माण लंबे समय से होता रहा है। अब क्राफ्ट का बेस सिस्टम नौसेना और कोस्ट गार्ड की मदद से तैयार किया जाएगा। इसके लिए इसी महीने टीम निर्माणी आएगी। उनकी जरूरत के मुताबिक बेस सिस्टम तैयार किया जाएगा। हावर क्राफ्ट पानी, जमीन, कीचड़ और घास पर चलने में सक्षम होता है। समुद्र या विशेष ऑपरेशन में हावर क्राफ्ट मददगार साबित होते हैं।

अगले कुछ माह में ब्रेक पैराशूट के होंगे फील्ड ट्रायल

एडवांस तेजस लड़ाकू विमान के ब्रेक पैराशूट का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया गया है। अगले कुछ महीनों में इसके फील्ड ट्रायल शुरू किए जाएंगे। साथ ही हावर क्राफ्ट के बेस सिस्टम को पहली बार बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। हावर क्राफ्ट एक नया काम होगा। रबर उत्पाद निर्माणी में पहले से ही बनाए जा रहे हैं।

देवरानी से कहासुनी के बाद महिला ने जहर खाकर दी जान

बांदा, संवाददाता। देवरानी से हुई कहासुनी के बाद महिला ने जहर खा लिया। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के मवई बुजुर्ग गांव निवासी सुखतीरथ (37) का शनिवार को देवरानी से घरेलू बात पर विवाद हो गया। कहासुनी से आहत होकर उसने जहर खा लिया। इससे उसकी मौत हो गई। मौसेरे भाई महेश यादव ने बताया कि सुखतीरथ और उसकी देवरानी रेखा आपस में सगी बहनें हैं। घर में हुए घरेलू विवाद पर दोनों एक–दूसरे से झगड़ गईं थीं। इसी के चलते सुखतीरथ ने आत्मघाती कदम उठाया है। सुखतीरथ चार साल से पेट दर्द से परेशान भी रहती थी। कई जगह इलाज भी कराया गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। सुखतीरथ के पति श्यामचरन यादव गांव में रहकर खेती किसानी करते हैं। पिता के पास 30 बीघा जमीन है। सुखतीरथ का मायका बबेरू कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव में है। पिता रामशरन यादव ने बताया कि दोनों बहनें आपस में झगड़ गईं थीं। शहर कोतवाल पंकज सिंह ने बताया कि परिजन घरेलू विवाद बता रहे हैं। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।

रात में दुकान खोलने से मना करने पर चाचा–भतीजे को पीटा

बांदा, संवाददाता। दुकानदार ने रात में दुकान खोलने से मना किया तो तीन लोगों पर दुकानदार पर हमला कर दिया। फरसे से वारकर उसे लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने दो लोगों का शांतिभंग में चालान किया है। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के पून गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने बताया कि उसकी घर में ही किराना की दुकान है। शनिवार की रात गांव के लखन यादव, राजाराम यादव व गनेशा यादव आए और दुकान खोलने के लिए कहा। उसने दुकान खोलने से मना किया तो उन्होंने राजेंद्र को पीट दिया। बचाने आए भतीजे आशु पर फरसे से हमला कर दिया, जिससे लहूलुहान हो गया। आशु को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। राजेंद्र का कहना है कि आरोपी उनसे रंजिश रखते हैं। कई बार पहले भी मारपीट कर चुके हैं, जिसका मुकदमा भी न्यायालय में चल रहा है। राजेंद्र का कहना है कि पुलिस ने गनेशा और लखन को पकड़ लिया। उधर, कोतवाल राजकुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की गई है। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पिता पर मां की हत्या का आरोप लगाने वाले मासूम बेटे की मौत, बेटी की हालत गंभीर

कानपुर, संवाददाता। पिता पर मां की गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगाने वाले आठ साल के बेटे की सोमवार तड़के संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बृहस्पतिवार रात को मां की मौत के बाद बच्चे ननिहाल चले गए थे। शनिवार को ही आरोपी पिता अच्छी परवरिश और खेती उनके नाम करने की बात कहकर बच्चों को ननिहाल से ककवन स्थित पैतृक गांव ले आया था। रात में खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ने पर उसने बेटे–बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां बेटे की मौत हो गई और बेटी की हालत गंभीर है। ननिहाल पक्ष के लोगों ने पुलिस को तहरीर देकर पिता पर जहर देने का आरोप लगाया है। मूलरूप से ककवन थाना क्षेत्र के सकरवां के रहने वाला रिक्शा चालक धर्मेंद्र कल्याणपुर के कश्यपनगर में पत्नी विनीता (28) व बेटे शनि (8) और चार साल की बेटी प्रीति के साथ रहता था। 11 जुलाई की रात संदिग्ध हालात में विनीता की मौत हो गई थी। इस दौरान बेटे शनि और बेटी प्रीति ने पुलिस को गवाही देते हुए पिता पर ही मां को बेरहमी से पीटने और साड़ी से गला घोटकर हत्या का आरोप लगाया था। कल्याणपुर पुलिस ने धर्मेंद्र को हिरासत में भी ले लिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ न होने और किसी की ओर से तहरीर न मिलने पर उसे छोड़ दिया था। शनिवार को धर्मेंद्र कानपुर देहात के मैथा स्थित ससुराल गया और दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश करने का वायदा कर गांव ले आया। यहां रविवार तड़के दोनों बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ी तो वह स्थानीय सीएचसी ले गया, जहां बेटे शनि को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस बीच ननिहाल पक्ष को किसी ने घटना की खबर दे दी। उन्होंने पुलिस को सूचना देते हुए सीएचसी से प्रीति को पहले कल्याणपुर के निजी अस्पताल पहुंचाया और फिर वहां से हैलट ले गए, जहां आईसीयू में वह जिंदगी की जंग लड़ रही है। उधर, परिजनों की ओर से दी तहरीर में दोनों बच्चों को जहर देने का आरोप लगाए जाने पर ककवन व कल्याणपुर थाना समेत पुलिस की पांच टीमें आरोपी पिता धर्मेंद्र की तलाश में जुट गई हैं।

आरोपी की तलाश में लगी टीमें

महिला के मायके वालों ने धर्मेंद्र व उसके परिवार वालों से लिखित समझौता कर बच्चे उसके हवाले किए थे। किशोर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अस्पताल में भर्ती बच्ची की स्वैब (लार) रिपोर्ट आने पर मौत का कारण स्पष्ट होगा। तब तक तहरीर के आधार पर धर्मेंद्र की तलाश में टीमें लगाई गई हैं।

बड़ी लापरवाही, बच्चों ने जिसके खिलाफ दी गवाही, उसी को सौंप दिए

इस घटना के बाद बच्चों की नानी राम दुलानी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना कार्रवाई किए ही उनकी बेटी की मौत का कारण बनने वाले आरोपी धर्मेंद्र को छोड़ दिया। कहा कि अगर पुलिस आरोपी जितेंद्र को थाने से न छोड़ती तो ये घटना नहीं होती। हालांकि इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि जब बच्चों ने पिता के खिलाफ पुलिस में गवाही दी थी तो ननिहाल पक्ष ने भी क्यों उन्हें धर्मेंद्र के सुपुर्द कर दिया।

बिन बताए शव दफनाने की चल रही थी तैयारी

रामदुलारी के अनुसार रविवार सुबह सकरवां गांव निवासी कल्लू से सूचना मिली कि शनि की मौत हो गई है। उसका शव दफनाने की तैयारी चल रही है। इसके बाद वह परिवार के साथ बेटी की ससुराल पहुंची और अंतिम संस्कार को रुकवा दिया। सूचना पर ककवन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

पुलिस की मौजूदगी में हुआ था दोनों पक्षों में समझौता

बिसरा की रिपोर्ट, मारपीट के निशान न मिलने और किसी के तहरीर न देने की वजह से पुलिस ने विनीता के परिवार और जितेंद्र के बीच समझौते की पहल की थी। शनिवार देर शाम ही दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया। इस दौरान धर्मेंद्र ने बच्चे के नाम कुछ जमीन कराने की बात भी कही थी।

चंबल नदी पर सिग्नेचर पुल के निर्माण में विभागीय बाधा

इटावा, संवाददाता। चंबल नदी पर लगभग दो साल पहले सिग्नेचर पुल बनवाने की स्वीकृति दी गई। इसके लिए शासन स्तर से 276 करोड़ रुपये का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया, लेकिन वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) न मिलने से पुल का निर्माण कार्य अब शुरू नहीं किया जा सका है। मध्यप्रदेश को जिले से जोड़ने के लिए चंबल नदी पर लगभग 70 साल पुराना पुल बना है। इसकी अवधि अधिक हो जाने की वजह से आए दिन क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसे में पुल को बंद भी करना पड़ता है। बीते लगभग डेढ़ साल से पुल बंद था, हाल में ही नियमों के साथ खोल गया था। भिंड, ग्वालियर होकर मध्यप्रदेश में जिले के लोग चंबल पार करके प्रवेश करते हैं। इस रास्ते में चंबल नदी पर लगभग 800 मीटर का 70 साल पुराना पुल बना हुआ है। इससे ही सभी का आवागमन रहता है। लेकिन पुल पुराना होने और इस पर ओवरलोड वाहन निकलने की वजह से कई क्षतिग्रस्त हो चुका है। लगभग डेढ़ साल पहले प्रशासन की ओर से इसे बंद भी करा दिया था। जिले की मध्यप्रदेश से आवाजाही प्रभावित हो गई थी। लोगों को चकरनगर होते हुए लगभग 100 किलोमीटर का चक्कर लगाकर मध्यप्रदेश जाना पड़ रहा था। इन परिस्थितियों को देखते हुए सदर विधायक सरिता भदौरिया ने उक्त पुल के समकक्ष एक नया पुल बनवाने की मांग की थी। लोगों की परेशानी को देखते हुए शासन ने भी इसे लगभग दो साल पहले स्वीकृति दे दी थी। ऐसे में जल्द ही इस सिग्नेचर पुल के बनने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद थी। इसके लिए शासन ने लगभग 276 करोड़ रुपये का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया था। पुल निर्माण के बीच में वन विभाग की जगह होने की वजह से उसकी ओर से एनओसी नहीं मिल सकी है। ऐसे में पुल के निर्माण की प्रक्रिया दो साल से रुकी हुई है।

कई बार किए जा चुके प्रयास

राष्ट्रीय मार्ग खंड के अधिशासी अभियंता मुकेश ठाकुर ने बताया कि शासन से नए फोरलेन पुल का बजट विभाग को मिल चुका है। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिर्फ चंबल सेंक्चुअरी की एनओसी का इंतजार है।

कई बार प्रयास के बाद भी एनओसी नहीं दी जा रही है। हमारी ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। एनओसी मिलते ही काम को शुरू कराया जाएगा। पुल के बीच में वन विभाग की जगह बीच में आ रही है।

तालाब की खोदाई में हुई सरकारी पैसे की बंदरबांट

मेरठ, संवाददाता। हसनपुर लुहारी गांव में तालाब की खोदाई के मामले में गड़बड़झाला सामने आया है। ग्राम पंचायत ने गांव के बच्चा श्मशान की भूमि पर कीचड़ डालकर भराव का नाम देकर दो लाख 80 हजार रुपये निकाल लिए। वहीं उक्त कीचड़ को मुफ्त बच्चा श्मशान पर डाला गया था। कुछ महीने पहले ग्राम पंचायत की ओर से गांव के नया बांस मोहल्ला स्थित सरकारी तालाब की खुदाई कराई थी। यहां से कीचड़ निकालकर ग्राम पंचायत की ओर से बच्चा श्मशान की भूमि पर डाल दिया। यह मामला गांव में तूल पकड़ गया और लोगों ने बच्चा श्मशान की भूमि पर कीचड़ डालने का विरोध किया। उस समय ग्राम पंचायत सचिव ने कहा था कि भराव करने के लिए मिट्टी डाली गई थी। खोदाई के पांच सौ मीटर के अंदर मिट्टी डाली गई है तो यह कार्य ठेकेदार द्वारा निशुल्क किया गया। हालांकि, जिस तालाब से खोदाई कर कीचड़ यहां डाला गया था, वहां विकास कार्य करने के नाम पर नौ लाख रुपये का बजट निकाला गया। बावजूद इसके अब फिर ग्राम पंचायत ने बच्चा श्मशान में मिट्टी का भराव करने के नाम पर दो लाख 80 हजार रुपये का बजट पास कराया है। अब उसी काम का ग्राम पंचायत ने दोबारा पैसा निकालने की करवाई शुरू कर दी है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।